पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक अपील वाद (खं.पी.) संख्या 269

थाना कांड संख्या-246 वर्ष-2011 थाना-रामनगर जिला-पश्चिम चंपारण से उत्पन्न

==

जमाल अख्तर, पुत्र- स्व. आशिक अली, निवास ग्राम- इदगाह मश्जिद रामनगर, थाना-रामनगर, जिला- पश्चिमी चम्पारण

......................अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य

..........प्रत्यर्थी

==

साथ में

2023 का आपराधिक अपील वाद (खं.पी.) संख्या -295

थाना कांड संख्या-246 वर्ष-2011 थाना-रामनगर जिला-पश्चिम चंपारण से उत्पन्न

==

मुन्नी खातून ऊर्फ मुन्नी निशा, पुत्र- स्व. शाफिक दिवान ऊर्फ स्व. शैख हुशमुददीन, निवासी- ग्राम एवं पोस्ट ऑफिस- जोगिया, थाना- रामनगर, स्थायी निवास- ग्राम-नरैनपुर, थाना-रामनगर, जिला- पश्चिमी चम्पारण

....................अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य

..................प्रत्यर्थी

==

साथ में

2023 का आपराधिक अपील वाद (खं.पी.) संख्या -356

थाना कांड संख्या-246 वर्ष-2011 थाना-रामनगर जिला-पश्चिम चंपारण से उत्पन्न

==

सेराजुल दिलेर ऊर्फ मो. सेराजुल अंसारी, पुत्र- स्व. अली हुसैन अंसारी, निवासी- ग्राम पैन टोला, थाना- रामनगर, जिला- पश्चिमी चम्पारण

................अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य

..............प्रत्यर्थी

==

उपस्थिति :

(अपराधिक अपील वाद (खं.पी.) सं. 269/2023)

अपीलार्थी की ओर से : श्री अबदूल मन्नान खान, अधिवक्ता

श्री अलामा अब्दूल कादिर जमाल फरिदी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री विनाद बिहारी सिंह, अपर लोक अभियोजक

(अपराधिक अपील वाद (खं.पी.) सं. 295/2023)

अपीलार्थी की ओर से : श्री अबदूल मन्नान खान, अधिवक्ता

श्री अलामा अब्दूल कादिर जमाल फरिदी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री परमेश्वर मेंहता, अपर लोक अभियोजक।

(अपराधिक अपील वाद (खं.पी.) संख्या-356/2023)

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रतिक कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री अभिमन्यू शर्मा, अपर लोक अभियोजक।

==

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 376/120B, 376(2)(g)—अभियोजिका के साथ अपीलकर्ता -1 और अपीलकर्ता -3 द्वारा अपीलकर्ता -2 की सक्रिय सहायता से सामूहिक बलात्कार किया गया और अभियोजिका द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई—सूचना देने वाले ने एक राजनीतिक व्यक्ति के प्रभाव में अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसकी अपीलकर्ताओं के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी और अभियोजिका के साक्ष्य और उसके करीबी रिश्तेदारों के साक्ष्य के बीच सामग्री असंगतियाँ हैं—अभियोजन पक्ष ने प्राथमिकी दर्ज कराने में अभियोजिका की ओर से एक महीने की अत्यधिक देरी को स्पष्ट करने में विफलता दिखाई और अभियोजन पक्ष यह भी साबित करने में असफल रहा कि अभियोजिका ने कथित घटना के कुछ दिन बाद अपने पति की सहायता से एक निजी अस्पताल में चिकित्सा उपचार कराया था—अभियोजिका के आचरण के खिलाफ प्रतिकूल राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त सामग्री है—विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों को सही दृष्टिकोण में नहीं समझा—आपराधिक सजा के खिलाफ अपील की गई निर्णय और सजा के खिलाफ अपील की गई आदेश को रद्द किया जाता है और सभी अपीलों में अपीलकर्ताओं को आरोपित अपराधों से संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है—अपीलें स्वीकृत की गईं।

(पैरा 19 से 29)

*(2012) 8 एससीसी 2021; (2016) 9 एससीसी 1; (2012) 4 एससीसी 379—**संदर्भित किया गया***

==

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह)

दिनांक-01-07-2024

ये तीनों अपीलें एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इनका निर्णय एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. यह अपील, बगहा, पश्चिम चंपारण के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-। द्वारा सत्र परीक्षण वाद संख्या 344/2014 में, जो रामनगर थाना कांड संख्या 246/2011 से उत्पन्न हुआ था, दिनांक 17.02.2023 को दिए गए दोषसिद्धि के फैसले और दिनांक 24.02.2023 को पारित सजा के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता मुन्नी खातून उर्फ मुन्नी निशा को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में भा.दं.सं.) की धारा 376/120 बी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और शेष अपीलकर्ताओं, अर्थात जमाल अख्तर और सेराजुल डीलर उर्फ सेराजुल अंसारी को भा.दं.सं. की धारा 376(2) (जी) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। अपीलकर्ता मुन्नी खातून उर्फ मुन्नी निशा को दस वर्ष की अवधि के सश्रम कारावास के साथ-साथ 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बाकी दो अपीलकर्ताओं को भा.दं.सं. की धारा 376(2)(जी) के तहत आजीवन कारावास के साथ 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और जुर्माना न चुकाने पर उन्हें छह महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटने का निर्देश दिया गया है।

3. यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ताओं के साथ एक सह-आरोपी शेख हसमुद्दीन पर भी आरोप लगाया गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और उसके खिलाफ विचारण न्यायालय के दिनांक 13.04.2022 के आदेश के अनुसार मुकदमा समाप्त हो गया। सभी अपीलकर्ताओं पर भा.दं.सं. की धारा 376/120 बी के तहत अपराध के लिए आरोप लगाए गए और अपीलकर्ता जमाल अख्तर और सेराजुल डीलर @ सेराजुल अंसारी पर भा.दं.सं. की धारा 376(2)(जी) के तहत अपराध के लिए अलग से आरोप लगाए गए।

अभियोजन का सार :-

4. अभियोजन पक्ष की कहानी का सार यह है कि 11.08.2011 को लगभग 8:00 बजे, अपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 295/2023 मे अपीलकर्ता/अभियुक्त (इसके बाद "ए-2" के रूप में संदर्भित) *मिस्कार टोली* में सूचिका (इसके बाद पीड़िता/सुचिका के रूप में संदर्भित) के निवास पर पहुंची और पीड़िता से कहा कि वह उसके साथ *उपप्रमुख* के घर चले जहां पीड़िता का पति (नूरूल होदा) ए-2 के अनुसार मौजूद था। उसने सूचक/पीड़िता को आगे बताया कि एक घटना हुई है जिसके संबंध में बात की जाएगी। ए-2 पर भरोसा करते हुए, पीड़ित/अभियुक्त शेख हसमुद्दीन के निवास *(डेरा)* पर गई, लेकिन उसे उसका पति नसरूल होदा नही मिला, वहां उसकी मुलाकात शेख हसमुदीन और इसराफिल से हुई लेकिन उसे देखने के बाद, वे लोग सूचक/ पीडिता से यह कह कर घर चले गए कि वह अपनी पति का इन्तजार करे, जो वाहन से आने वाला है, उसके आने के बाद बात करेंगे। सूचक ने आगे आरोप लगाया कि रात 10:00 बजे तक उसका पति नहीं आया और वह अचानक बुलाने का कारण समझने में असमर्थ थी। इसलिए, उसने ए-2 से उसे अपने निवास पर छोड़ देने के लिए कहा, जिस पर ए-2 ने उससे पुछा कि वह शेख हसमुदीन के साथ रहने का आनंद क्यो नही ले रही है। इसी बिन्दू पर सुचक और ए-2 के बीच एक मौखिक विवाद हुआ और इसी बीच, अपीलकर्ता जमाल अख्तर और सेराजुल डीलर (जिन्हें क्रमशः ए-1 और ए-3 के रूप में संदर्भित किया गया है) कमरे में प्रवेश किया और उन्होंने गंदी भाषा का उपयोग करते हुए पीड़िता को गाली देना शुरू कर दिया और ऐसा करते समय उन्होने उसके साथ जबरदस्ती किया और उसके मुंह को उसके *दुपट्टे* से बांध दिया। उसके हाथ और पैर को कस कर पकड लिया और उसके बाद उन्होने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया और ए-2 की सक्रिय सहायता से एक-एक करके उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।

5. आरोप के अनुसार, पीड़िता को अपीलकर्ताओं ने अपनी हिरासत में रखा था और लगातार दो दिन और दो रात तक उसका यौन उत्पीड़न किया गया और इस दौरान जब पीड़िता बेहोश हो गई तो आरोपियों ने उसे होश में लाकर फिर से उसके साथ बार-बार और क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया। लेकिन सौभग्य से तीसरे दिन शाम को आरोपियो के चंगुल से भागने में सफल रही और स्थानीय पुलिस स्टेशन गई और अपनी आप बीती सुनाई। आरोपियों के नाम सुनते ही पुलिस ने उसे गाली देना शुरू कर दिय, उसे सलाखों के पिछे डालने की धमकी दी और उसे थाने से बाहर जाने को कहा। इसके बाद वह हरीनगर रेलवे स्टेशन गयी और ट्रेन से सवार होकर मुजफ्फरपुर गई। वहाँ उसने कुछ दवा ली और भीख माँगकर पैसा इक्कठा कर *हिजाब (नकाब)* खरीदी। उसके बाद वह मुजफ्फरपुर छोड़कर रामनगर आ गई। वहाँ वह अपने पति से मिली और उसे पुरी घटना बताई। उसका पति डर गया और उसने कहा कि आरोपी व्यक्ति अमीर आदमी है उसका स्तर और प्रभाव ऊचा है और वे उन्हें जान से मार सकते है। अंत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्ति उसे परेशान कर रहे थे और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दवाव बना रहे थे और उसके मना करने पर कथित घटना घटी। उसने आगे बताया कि पुलिस उप महानिरीक्षक (डी.आई.जी) के पास गई थी और उनके आदेश पर मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दायर किया गया। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने झूठे आरोप लगाकर उसके पति को पड़तारित किया। जिसके कारण उसे रामनगर में कई किराये के मकान बदलने पड़े। सूचिका के अनुसार वह अपने पति के दूसरी पत्नी है और पहले पत्नी से अच्छा संबंध न रहने के कारण वह रामनगर में किराये के मकान में रहती है।

6. उपरोक्त अभियोजन की कहानी और आरोपों का वर्णन करते हुए, सूचक/पीड़िता ने रामनगर पुलिस स्टेशन में एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श- 'पी -3' दर्ज की, जिसे मधुकर राय नामक व्यक्ति ने लिखा था, उस आधार पर, पंजीकरण संख्या

246/2011 के तहत भा.दं.सं. की धाराओं 376 और 120 बी के तहत औपचारिक प्राथमिकी पंजीकृत किया गया और कार्यवाई शुरू की गई।

7. जांच पूरी होने पर, पुलिस ने अपीलकर्ताओं और सह-अभियुक्त शेख हसमुद्दीन (अब मृत) के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 376 और 120 बी के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया और एक व्यक्ति, इशरफिल, जिसका नाम प्राथमिकी में था, को पुलिस द्वारा आरोपित नहीं किया गया। विद्वान एसीजेएम, बगहा ने कथित अपराधों का संज्ञान लिया और अपीलकर्ताओं के मामले को परीक्षण के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

8. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाहों से पूछताछ की तथा छः दस्तावेजों को प्रमाणित किया तथा उन्हें प्रदर्श के रूप में चिन्हित कराया जो निम्नानुसार हैं:-

अभियोजन पक्ष के 11 गवाहों की सूची :-

क्रम संख्या	**नाम**	**गवाह के प्रकृति**
अभियोजन साक्षी सं.1	XXXXXXXXXXX	प्रत्यक्षदर्शी गवाह (सूचिका)
अभियोजन साक्षी सं.2	मुरतूजा खान	पुलिस गवाह
अभियोजन साक्षी सं.3	मेहरूण नेशा ऊर्फ बिलाई खातून	पुलिस गवाह
अभियोजन साक्षी सं.4	शाहनवाज मिस्त्री	पुलिस गवाह
अभियोजन साक्षी सं.5	शमीम अख्तर हावारी	दुसरा अनुसंधानकर्ता
अभियोजन साक्षी सं.6	अनवरूल हक	पुलिस गवाह
अभियोजन साक्षी सं.7	शेख रेयाज अमीन	पुलिस गवाह
अभियोजन साक्षी सं.8	नूरूल होडा	पुलिस गवाह
अभियोजन साक्षी सं.9	किशोरी चौधरी	प्रथम अनुसंधानकर्ता

अभियोजन साक्षी सं.10	डॉ. रश्मिनंद कलियार	चिकित्सा विशेषज्ञ साक्षी
अभियोजन साक्षी सं.11	मधुकर राय	अन्य साक्षी

अभियोजन द्वारा अंकित प्रर्दश :-

क्रम संख्या	प्रर्दश सं.	विवरण
1	प्रर्दश पी-1/ अ.सा.-9	श्री कृष्णनंदन झा थाना अध्यक्ष रामनगर का लिखित सूचना रिपोर्ट पर हस्ताक्षर।
2	प्रर्दश पी-2/अ.सा.-9	थाना अघ्यक्ष और श्री गणेश सिंह का प्रथम सुचना रिपोर्ट पर हस्तलेख और हस्ताक्षर।
3	प्रर्दश पी-3/अ.सा. -11	प्रथम सुचना रिपोर्ट पर अभियोजन साक्षी संख्या 11 मधुकर राय का हस्तलेख एवं हस्ताक्षर।
4	प्रर्दश पी-4	आरोप पत्र संख्या 285/2012 की कार्बन कॉपी।
5	प्रर्दश पी-5	**पीडिता** के बयान अंर्तगत धारा 164 द.प्र.स.की कार्बन कॉपी।
6	प्रर्दश पी-6/अ.सा.-10	अभियोजन साक्षी सं.10 का **पीडिता** के चिकित्सीय रिपोर्ट पर हस्तलेख एवं हस्ताक्षर।

9. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पुरा होने के बाद अपीलकत्ताओं के ब्यान को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया और उन्हें अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से उनके खिलाफ मौजूद परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर दिया गया। अपीलकत्ताओं ने उक्त परिस्थितियों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताया और अपने बचाव में कोई विशेष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

10. बचाव में अपीलकत्ताओं ने केवल एक गवाह अर्थात डॉ. ब्रजबिहारी प्रसाद, चिकित्सक, नव जीवन नसिर्ग होम, बेतिया से डी.डब्लू.-1 1 के रूप में परीक्षण कराया, जिसने चिकित्सीय रिपोर्ट जो ए-2 को होने का दावा करती है, पर अपने हस्तलेख और हस्ताक्षर को पहचाना, जिसे दस्तावेजी साक्ष्य 'डी-ए' के रूप में प्रर्दश अंकित किया गया।

<u>अपीलकत्ताओं की ओर से प्रस्तुतिकरण-</u>

11. अपीलकत्ता सेराजुल डीलर उर्फ सेराजुल अंसारी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक कुमार ने तर्क दिया हैं कि मुकरने के दौरान सूचिका के पति सहित महत्वपूर्ण गवाह मुकर गये है और सूचिका की ओर से अपनी प्राथमिकी दर्ज करने की एक महीने की अत्यधिक देरी हुई है और अभियोजन पक्ष द्वारा देरी का उचित कारण नहीं बताया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि सूचिका ने मधुकर नामक व्यक्ति के कहने पर राजनीतिक प्रतिद्वांदिता के कारण यह मामला दर्ज कराया है और अभियोजन द्वारा कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं दिया गया है। जबकि अभियोक्ता की गवाही के अनुसार कथित घटना के कुछ दिन बाद ही उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, वास्तव में अभियोक्ता का कथित घटना के समय आचरण संदिग्ध था।

12. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विचारण न्यायालय में मुख्य रूप से सूचिका के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए अपीलकत्ताओं को दोषित ठहराया, जोकि विरोधाभासों से भरा है और अभियोजन पक्ष द्वारा किसी स्वतंत्र गवाह की परीक्षा नहीं करायी गई है। यह भी कहा गया है कि सूचिका को एक उत्कृष्ट गवाह नहीं माना जा सकता क्योंकि उसका ब्यान आरोप के अनुरूप नहीं था और कई परिस्थियां है जो अपराध की सत्यता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है। प्राथमिकी दर्ज करने में एक महीना की अत्यधिक देरी अपने आप में सूचिका द्वारा लगाये गये आरोपो की सत्यता

के बारे में संदेह पैदा करती है। इन दलीलों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने ***राय संदीप बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)*** के मामलों में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है, जो ***(2012) 8 एससीसी 2021*** में रिपोर्ट किए गए और **मनोज कुमार शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2016) 9 एससीसी 1** में रिपोर्ट किए गए।

13. अपीलकत्ता मुन्नी खातून उर्फ मुन्नी निशा (ए-2) और जमाल अखतर (ए-1) की ओर पेश विद्वान वकील श्री अब्दुल मन्नान खान ने अपीलकर्ता सेराजुल डीलर (ए-3) की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दलीलों को स्वीकार किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्राथमिकी में वर्णित अभियोजन पक्ष का मामला बेहद अविश्वसनीय है और अभियोजन का साक्ष्य स्वतः विरोधाभासी है और उनका स्वयं का केस अभियोजन साक्ष्यों के द्वारा खंडित हो जाता है।

<u>प्रतिवादी/राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>: -

14. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री बिनोद बिहारी सिंह, श्री परमेश्वर मेहता और श्री अभिमन्यु शर्मा ने इन अपीलों का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि दोषसिद्धि केवल सुचक के साक्ष्य के आधार पर ही हो सकती है और वर्तमान मामले में सूचिका के साथ अभियुक्त/अपीलकर्ता ए-1 और ए-3 ने अपीलकर्ता ए-2 की सक्रिय सहायता से सामूहिक बलात्कार किया था और प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी को अभियोजन द्वारा उचित रूप से समझाया गया था और अपीलकर्ताओं के वकीलों द्वारा बताए गए विरोधाभास मामूली और नजरअंदाज करने योग्य हैं। अपीलकर्ताओं को आरोपित अपराधों के लिए सही ढंग से दोषी ठहराया गया है और ये अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं।

<u>विश्लेषण और चर्चा</u>

15. हमने दोनों पक्षों को सुना, और इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है। यौन उत्पीड़न से जुड़े अपराध आम तौर पर तब किए जाते हैं जब पीड़िता अकेली पाई जाती है या किसी सुनसान जगह पर होती है, जहां पीड़िता को आरोपी ले जाता है, वहां, ऐसे अधिकांश मामलों में, पीड़िता ही अपराध की चश्मदीद गवाह पाई जाती है और अक्सर उसे एक बेहतरीन गवाह माना जाता है। हालांकि, यौन उत्पीड़न के अपराधों में, सूचिका के साक्ष्य के आधार पर ही दोषसिद्धि हो सकती है, यदि वह पूरी तरह से विश्वसनीय, स्वाभाविक और अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप हो, लेकिन जहां उसके साक्ष्य में कुछ भौतिक असंगति दिखाई देती है या उसकी गवाही में कुछ भौतिक विरोधाभास दिखाई देते हैं या कुछ अन्य परिस्थितियां हैं जैसे कि एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी, मेडिकल साक्ष्य से पुष्टि न होना, तो ऐसी किसी भी स्थिति की उपस्थिति में, पीड़िता की गवाही की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***राय संदीप (उपरोक्त)*** के मामले में इस निर्णय के पैराग्राफ 22 में इस बारे में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि किसे "उत्कृष्ट गवाह" कहा जा सकता है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

*"**22.** हमारी राय मे ''उत्कृष्ट गवाह'' बहुत ही उच्च गुणवता और क्षमता का होना चाहिए, इसका बयान निर्विवाद होना चाहिए, ऐसे गवाह के बयान पर विचार करने वाली अदालत को बिना किसी हिचकिचाहट के इसे उसके अंकित मुल्य पर स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे गवाह की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, गवाह की स्थिति महत्वहीन होगी और जो प्रासंगिक होगा वह ऐसे गवाह द्वारा दिए गए बयान की सत्यता है। जो अधिक प्रासंगिक होगा वह बयान की शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी उस*

समय जब गवाह प्रारंभिक बयान देता है और अंततः अदालत के समक्ष बयान देता है, की संगति होगी। यह स्वाभाविक होना चाहिए और अभियुक्त के रूप में अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे गवाह के बयान में कोई झूठ नहीं होना चाहिए। गवाह को किसी भी लम्बाई और चाहे कितनी भी कठिन जिरह क्यों न हो, उसे झेलने की स्थिति में होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों और इसके अनुक्रम के बारे में किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस तरह के बयान का अन्य सभी सहायक सामग्रियों जैसे बरामदगी, इस्तेमाल किए गए हथियार, अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय के साथ सह-संबंध होना चाहिए। उक्त बयान को हर दूसरे गवाह के बयान से लगातार मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू किए जाने वाले परीक्षण के समान होना चाहिए, जहां परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी ऐसी कड़ी नहीं होनी चाहिए जो आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए अपराध का दोषी ठहराए। केवल तभी जब ऐसे गवाह का बयान उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी समान परीक्षणों को भी योग्य बनाता है, तब यह माना जा सकता है कि ऐसे गवाह को "उत्कृष्ट गवाह" कहा जा सकता है, जिसका बयान अदालत द्वारा बिना किसी पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक सटीक रूप से, अपराध के मुख्य स्पेक्ट्रम पर उक्त गवाह का बयान बरकरार रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी सहायक सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुएं, मुख्य विवरणों में उक्त बयान से मेल खानी चाहिए ताकि अपराध की सुनवाई करने वाली अदालत को मुख्य बयान पर भरोसा करने में सक्षम बनाया जा सके ताकि अपराधी को

आरोपित आरोप का दोषी ठहराने के लिए अन्य सहायक सामग्रियों को छाना जा सके।

17. इस सवाल पर कि *प्राथमिकी* दर्ज करने में देरी का क्या असर होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मनोज कुमार शर्मा (उपरोक्त)** के मामले में पैरा 30 में कहा कि *"प्राथमिकी दर्ज करने में देरी से अक्सर मामला उलझ जाता है, जो बाद में सोचा जाने वाला काम है। "देरी के कारण, प्राथमिकी न केवल सहजता के लाभ से वंचित हो जाती है, बल्कि एक रंगीन संस्करण या अतिरंजित कहानी पेश किए जाने का खतरा भी पैदा होता है। हमारी राय में, प्राथमिकी दर्ज करने में इस तरह की असाधारण देरी प्रतिवादी 2 द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है, जो किसी भी मामले में, प्रकृति में सामान्य हैं। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के लापरवाह और अस्पष्ट आरोप लगाकर प्रतिवादी 2 ने अपीलकर्ताओं को आपराधिक कार्यवाही में शामिल करने की कोशिश की है। हम इस बात पर दृढ़ राय रखते हैं कि इस प्राथमिकी के अनुसार अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसलिए, न्याय के हित में, प्राथमिकी को खारिज किया जाना चाहिए।"*

18. उपरोक्त टिप्पणी करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में अपने पहले के निर्णय का अनुसरण किया, जिसकी रिपोर्ट (2012) 4 एससीसी 379** में दी गई थी, जिसमें यह माना गया था कि:-

> "**12.** *आपराधिक मामले में प्राथमिकी एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान साक्ष्य है, हालांकि यह ठोस साक्ष्य नहीं हो सकता है। किसी अपराध के संबंध में प्राथमिकी को तुरंत दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य अपराध के घटित होने की परिस्थितियों, वास्तविक अपराधियों के नाम और*

उनकी भूमिका के साथ-साथ घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के नामों के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करना है। यदि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी होती है, तो यह सहजता का लाभ खो देता है, बड़ी संख्या में परामर्श/विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप रंगीन संस्करण, अतिरंजित विवरण या मनगढ़ंत कहानी पेश किए जाने का खतरा होता है। निस्संदेह, प्राथमिकी दर्ज करने में तत्परता सूचना देने वाले के संस्करण की सत्यता के बारे में एक आश्वासन है। एक त्वरित दर्ज की गई प्राथमिकी वास्तव में क्या हुआ है, और संबंधित अपराध के लिए कौन जिम्मेदार था, इसका प्रत्यक्ष विवरण दर्शाती है।"

19. इस मामले में सूचिका ने खुद ही प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में उसके द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, अपीलकर्ता ए-3, ए-1 और सह-आरोपी शेख हसमुद्दीन (अब मृतक) ने उसके साथ बलात्कार किया, जिसमें अपीलकर्ता ए-2 ने अन्य अपीलकर्ताओं की सहायता की। सूचिका ने मुख्य परीक्षा में कहा कि कथित घटना में इशराफिल नामक व्यक्ति ने भी उसके साथ बलात्कार किया। लेकिन मुख्य परीक्षा की शुरुआत में उसने अपराधियों में से एक के रूप में उक्त व्यक्ति का नाम नहीं बताया और यहां तक कि उसने प्राथमिकी में भी उसका नाम नहीं बताया। इस तरह, यह स्पष्ट है कि सूचिका ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने बयान में सुधार किया और इस संबंध में उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिससे उसके आरोपों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है।

20. अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता को साबित करने के लिए, अपीलकर्ताओं ने मुख्य रूप से उसके (सूचिका) संदिग्ध आचरण और एक व्यक्ति, अर्थात् मधुकर राय, जिसके साथ मृतक-अभियुक्त शेख हसमहद्दीन का राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी। इस संबंध में अपीलकर्ताओ के विद्वान वकीलों ने इस न्यायालय का ध्यान सूचिका के पति (अ.सा.-08) और जांच अधिकारी (अ.सा.-9) के बयानों की ओर किया है। दोनों गवाहों

के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर, हम सूचिका के आरोपों के संबध में उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए अपीलकर्तओं द्वारा उठाये गए आधारों में दम पाते हैं। लिखित प्राथमिकी (प्रदर्श-3) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिकी मधुकर नामक व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी। अ.सा.-4, शाहनवाज मिस्त्री ने गवाही दी है कि सूचिका के पति की तारा मास्टर नामक एक व्यक्ति से मित्रता है और कथित घटना के समय पीड़िता का पति मधुकर राय के अधीन ड्राइवर के रूप में काम करता था, जिसकी शेख हमुद्दीन (मृत आरोपी) के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी। सूचक के पति नूरुल होदा, जिससे अ.सा.-8 के रूप में परीक्षण की गई है, ने आरोपी हसमद्दीन और मधुकर राय के बीच चल रही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को स्वीकार किया और उसने यह भी स्वीकार किया कि कथित घटना के प्रासंगिक समय में वह महदुकर राय का कर्मचारी था। इस गवाह को एक महत्वपूर्ण गवाह माना जा सकता है क्योंकि उसे पीड़िता का पति बताया गया है और प्राथमिकी के अनुसार वह पहला व्यक्ति था जिसे अपनी पत्नी से कथित घटना के बारे मे सूचना मिली थी। इस गवाह के बयान के अनुसार उसके और उसकी पत्नी (सूचिका) के बीच अच्छे संबंध थे और वह शादी के समय से ही उसके साथ पत्नी के रूप में रह रही थी। उसकी गवाही से पता चलता है कि इस गवाह और सूचिका के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन गवाह ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया और अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। उसने मुख्य परीक्षा में कहा कि उसे ऐसी किसी घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जो उसकी पत्नी के साथ चार साल पहले हुई थी। उसने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराने से इन्कार किया है । हालाँकि गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था, लेकिन अपीलकर्ताओं की ओर से की गई जिरह में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि जैसा कि आरोप लगाया गया है, उसकी पत्नी के साथ कुछ भी नहीं हुआ और मधुकर राय ने एक सादे कागज पर अपनी पत्नी के अंगुठे का

निशान लिया था, जिसका इस्तेमाल बाद में उसने अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में किया, जिनके साथ उक्त मधुकर राय की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी। इस तरह, इस गवाह का साक्ष्य पूरी तरह से आरोप के खिलाफ जाता है और अपीलकर्ताओं के बचाव को मजबूत बनाता है, जिसकी चर्चा ऊपर की गई है।

21. यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जांच अधिकारी, जिसकी अ.सा.-5 के रूप में जांच की गई थी, का भी यह मानना था कि सूचिका ने अपना मामला दुर्भावना से दर्ज कराया था और इस संबंध में, उन्होंने स्वीकार किया कि जांच के दौरान, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों, अर्थात् मेहरून निशा और मुर्तुजा खान (सूचिका के पिता) ने कहा कि अपीलकर्ता ए-1 और अभियुक्त (अब मृतक) शेख हसमुद्दीन को झूठा फंसाया गया था। गवाह ने अपनी गवाही में कहा कि अभियुक्तों के चरित्र के सत्यापन के लिए, उन्होंने कई व्यक्तियों से पूछताछ की, लेकिन उनमें से किसी ने भी अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया और उनके अनुसार, अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं का चरित्र अच्छा था। इस प्रकार, इस गवाह का साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के विरुद्ध जाता है।

22. अभियोजन की गवाही के अनुसार, इशरफिल नामक व्यक्ति ने भी आरोपी शेख हसमूददीन के साथ मिलकर उसके साथ बालात्कार किया और अपीलकर्ता ए-2 ने घटना में अन्य आरोपियो कि सहायता की। सूचिका द्वारा इसराफिल और हसमुददीन के विरूद्ध लगाया गया बालात्कार का आरोप अविश्वसनीय प्रतीत होता है क्योंकि सूचिका के पिता अ.सा.-2 के मुर्तूजा खान के अनुसार इसराफिल अपीलकर्ता मुन्नी खातुन का पुत्र है और मृतक आरोपी हसमुददीन अपीलकर्ता ए-2 का पति था। यदि हम अभियोजन की कहानी पर विश्वास करें तो यह बात सामने आती है कि पिता और पुत्र दोनो ने सूचिका के साथ बालात्कार किया और इस घटना में मां/पत्नी ने बालात्कार करने मे सहयोग किया, जो कि साक्षियों के बयान से सही प्रतीत नहीं होता है।

23. सूचिका ने अपनी प्राथमिकी में उल्लेख किया है कि उसने सबसे पहले शेख हसमुद्दीन और इशराफिल को आरोपी शेख हसमुद्दीन के घर पर पाया, जो अपीलकर्ता ए-2 के साथ पीड़िता को देखकर तुरंत घर से चले गए और कहा कि उसका पति वाहन पर आ रहा है। लेकिन सूचिका ने विचारण न्यायालय के समक्ष इस तथ्य का खुलासा नहीं किया और उसने गवाही दी कि जब वह ए-2 के साथ शेख हसमुद्दीन के घर पहुंची तो वहां कोई मौजूद नहीं था। इसलिए, सूचिका द्वारा अपनी प्राथमिकी में वर्णित कहानी और अभियुक्त व्यक्तियों के साथ सूचिका की पहली मुलाकात के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के बीच एक महत्वपूर्ण विरोधाभास दिखाई देता है। यह विरोधाभास अभियोजन पक्ष के मामले को गंभीर रूप से प्रभावित करता है,

24. सूचिका ने अपनी प्राथमिकी में खुलासा किया कि अभियुक्त उसके पति को प्रताड़ित कर रहा था और उस पर यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा था और उस उत्पीड़न के कारण उसे कई बार अपना किराए का मकान बदलना पड़ा। लेकिन विचारण न्यायालय के समक्ष सूचिका ने उक्त तथ्य के विपरीत बयान दिया। उसने जिरह के पैरा-5 में कहा कि वह अपने पति के साथ शादी के समय से लेकर मामले के शुरू होने तक *मिश्कर टोली* में रह रही थी। जब उससे इस बारे में पूछा गया तो उसने अपने किराए के मकान के मालिक का नाम नहीं बताया। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सूचिका ने जिरह के पैरा-6 में कहा कि वह अभियुक्त के घर एक बार भी नहीं गई। यह बयान प्राथमिकी में बताई गई अभियोजन पक्ष की कहानी के विपरीत है।

25. सूचिका के अनुसार, अभियुक्तगणों द्वारा उसके साथ लगातार दो दिनों तक बलात्कार किया गया तथा तीन व्यक्तियों ने उसके साथ बलात्कार किया तथा

अभियुक्तगणों के चंगुल से छूटकर मुजफ्फरपुर पहुंचने पर उसने भीख मांगकर कुछ पैसे का प्रबंध करके कुछ दवाइयां लीं। उसने जिरह के कंडिका-7 में कहा कि उसका रामनगर तथा मुजफ्फरपुर में इलाज नहीं हुआ, लेकिन उसी कंडिका में उसने कहा कि उसने दं.प्र.स. की धारा 164 के तहत अपने बयान में कहा था कि उसके पति ने उसका इलाज रामनगर के एक निजी अस्पताल में कराया था। इस प्रकार अभियोक्ता ने अपने इलाज के संबंध में सुसंगतता नहीं रखी तथा इसके अतिरिक्त, रामनगर में उक्त इलाज के संबंध में अभियोजन द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया।

26. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता के साथ आरोपी शेख हसमुद्दीन के घर पर दो दिनों तक लगातार दिन-रात बलात्कार किया। जांच अधिकारी, अ.सा.-9 ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पाया कि आरोपी हसमुद्दीन का घर दो मंजिला है और पहली मंजिल पर दो कमरे हैं, जहां बलात्कार की कथित घटना हुई थी। उनके अनुसार, घटनास्थल भीड़भाड़ वाले बाजार में स्थित है और उन्होंने कुछ लोगों के बयान दर्ज किए जिनकी दुकानें कथित घटनास्थल के पास हैं। अभियोजन पक्ष आरोपी हसमुद्दीन का पड़ोसी होने के नाते अपना साक्ष्य दर्ज करने के लिए उनमें से किसी को भी पेश करने में विफल रहा। इन व्यक्तियों का साक्ष्य घटना के प्रासंगिक समय के दौरान आरोपी शेख हसमुद्दीन के घर में संदिग्ध गतिविधि को साबित करने के लिए प्रासंगिक हो सकता है और यह अभियोजन पक्ष के खिलाफ जाता है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जांच अधिकारी/अ.सा.-9 की गवाही के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (डिप्टी एस.पी.) ने अपने पर्यवेक्षण नोट में यह राय दी कि अभियोक्ता ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण दुर्भावना से अपना मामला दर्ज कराया है और उन्होंने कथित घटना को झूठा मामला बताते हुए आरोपी के पक्ष में पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सिफारिश की। हालाँकि, जांच अधिकारी उक्त राय से

बाध्य नहीं था, लेकिन उसने कोई ठोस सामग्री नहीं दिखाई जिसके आधार पर उसने आरोपी को आरोप पत्र सौंपा।

27. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि सूचिका का चरित्र अच्छा नहीं है और इस संबंध में, इस न्यायालय का ध्यान सूचिका के पिता अ.सा.-2 के साक्ष्य की ओर आकर्षित किया गया है, जिन्होंने स्वीकार किया कि सूचिका का विवाह इम्तियाज खान नामक व्यक्ति से हुआ था और उनके विवाह से दो बच्चे पैदा हुए थे। गवाह ने आगे कहा कि इम्तियाज खान से दो बच्चों के जन्म के बाद, उसकी बेटी (सूचिका) नूरुल होदा के साथ भाग गई और फिर उसे वापस लाया गया लेकिन वह फिर से उक्त नूरुल होदा के साथ भाग गई। इस गवाह के अनुसार, अभियुक्त हसमुद्दीन और ए-1 (अपीलकर्ता) ने सूचिका की बरामदगी में मदद की। सचिका की मां (अ.सा.-3) ने भी इसी तरह का साक्ष्य दिया। दोनों गवाहों, जो सूचिका के माता-पिता होने के नाते करीबी रिश्तेदार हैं, ने सूचिका और नूरुल होदा के बीच वैवाहिक संबंध के बारे में कुछ नहीं कहा, जिसे अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार सूचिका का पति कहा जाता है। सूचिका ने अपने साक्ष्य में कहा कि उसके और उसके पूर्व पति इम्तियाज के बीच तलाक हो चुका है लेकिन इस संबंध में उसने कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया। इस संबंध में अनवारुल हक/अ.सा.-6 ने गवाही दी कि सूचक/अभियोक्ता नूरुल होदा की पत्नी है और उसने उनके *निकाहनामे* पर अपने हस्ताक्षर किए हैं और सूचक का विवाह (*निकाह*) कथित घटना के होने से सिर्फ एक या दो महीने पहले हुआ था। लेकिन सूचिका ने परीक्षण के दौरान और साथ ही विचारण न्यायालय के सामने भी उक्त *निकाहनामा* पेश नहीं किया, जब नूरुल होदा के साथ उसके वैवाहिक संबंध के बारे में उससे जिरह की गई थी। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि सूचिका के अनुसार, वह नूरुल होदा के साथ विवाह करने से पहले दो से तीन साल तक उसके साथ रह रही थी। ये तथ्य और सूचिका के माता-पिता का साक्ष्य

सूचिका के आचरण पर प्रश्नचिह्न लगाने के लिए पर्याप्त हैं और उसके साक्ष्य अन्य सबूतों के मूल्य को कम कर देंगे।

28. वर्तमान मामले में, कथित घटना 11.08.2011 और 12.08.2011 को किए गए हैं और प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता घटना के दो दिन बाद आरोपियों के चंगुल से भागने में सफल रही लेकिन उसके द्वारा प्राथमिकी घटना के एक महीने बाद 11.09.2011 को दर्ज कराई गई थी। हालांकि विलंब के संबंध में, अभियोजन पक्ष ने यह बचाव किया कि उसने आरोपियों के चंगुल से भागने के तुरंत बाद संबंधित पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रयास किया था लेकिन आरोपियों के प्रभाव के कारण उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई थी और उसने अपने प्रति परीक्षण के पैराग्राफ -8 में गवाही दी कि वह दो दिनों तक मुजफ्फरपुर में रही और वह अकेली अपना बयान दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गई थी और वह मुजफ्फरपुर से आने के एक साल बाद अपना बयान दर्ज कराने गई थी और उस अवधि के दौरान, वह मिश्कर टोली में रहती थी, उसने आगे कहा कि उसने घटना का सारा विवरण थाना प्रभारी को दिया, जिन्होंने विवरण नोट किया और लेखन पर उसका अंगूठा का निशान लिया इन बयानों से ऐसा नहीं लगता कि जब वह पुलिस के पास गई तो पुलिस ने उसका बयान दर्ज करने से इनकार कर दिया। सूचिका के अनुसार, रामनगर में पुलिस उपाधीक्षक का कार्यालय है, जहां वह अपराध के समय रह रही थी। सूचिका के साक्ष्य से ऐसा नहीं लगता कि उसने संबंधित पुलिस थाने द्वारा उसकी शिकायत दर्ज न करने के लिए उपाधीक्षक के समक्ष अपनी शिकायत उठाने का प्रयास किया। इसके अलावा, एफ.आई.आर. के अनुसार, सूचक ने पुलिस उप महानिरीक्षक (डी.आई.जी.) से मुलाकात की और उनके निर्देश पर उसने अपना लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त तथ्य का खुलासा सूचक ने एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी को स्पष्ट करने के लिए किया है क्योंकि उसके अनुसार, शुरू में संबंधित पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी ने उसकी

प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी, इसलिए उसे (डी.आई.जी.) के समक्ष उपस्थित होना पड़ा। लेकिन इस संबंध में, वह अपने साक्ष्य दर्ज करते समय विचारण न्यायालय के समक्ष चुपचाप रही और उसने यह बयान दिया कि उसने अपने पति को कथित घटना के बारे में तब अवगत कराया जब वह उससे मिली और उसके बाद, पुलिस थाने गई और अपना आवेदन दायर किया। इस प्रकार, सूचिका ने अपनी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए डी.आई.जी के पास जाने के तथ्य के बारे में विरोधाभासी बयान दिया। तदनुसार, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष बलात्कार की कथित घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज कराने में सूचिका की ओर से हुई अत्यधिक देरी को स्पष्ट करने में विफल रहा, जबकि सूचिका के पति का राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति मधुकर राय के साथ अच्छा संबंध था, जिसने प्राथमिकी लिखी थी जिसे बाद में पंजीकृत किया गया था।

निष्कर्ष:-

29. अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों पर चर्चा करने के बाद, हम इस विचार पर पहुंचे हैं कि अभिलेख पर यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि सूचक ने एक राजनीतिक व्यक्ति के प्रभाव में अपना मामला दर्ज कराया, जिसकी अपीलकर्ताओं के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी और सूचिका के साक्ष्य और उसके करीबी रिश्तेदारों के साक्ष्य के बीच भौतिक असंगतताएं हैं। अभियोजन पक्ष एक महीने की अत्यधिक देरी को स्पष्ट करने में विफल रहा जो सूचिका की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने में हुई और अभियोजन पक्ष सूचिका के चिकित्सा उपचार के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश करने में विफल रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कथित घटना के कुछ दिनों बाद अपने पति की सहायता से एक निजी अस्पताल में उपचार कराया था। सूचिका के आचरण के खिलाफ प्रतिकूल राय बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा। इस प्रकार, हम पाते हैं कि

अपीलकर्ताओं को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराने और सज़ा देने का निर्णय और आदेश, जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया था, अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की उचित समीक्षा किए बिना पारित किया गया था, इसलिए उन्हें रद्द किया जाता है और सभी अपीलों में अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देते हुए आरोपित अपराधों से बरी किया जाता है। ये अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

30. आप. अपील (खं.पी.) संख्या 269/2023 में अपीलकर्ता जमाल अख्तर और आप. अपील (खं.पी.) संख्या 356/2023 में अपीलकर्ता सेराजुल डीलर सेराजुल अंसारी हिरासत में हैं, इसलिए, यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाएगा।

31. अपीलकर्ता मुन्नी खातून उर्फ मुन्नी निशा जमानत पर है, इसलिए उसे जमानत बांड से उत्पन्न होने वाले दायित्व से मुक्त किया जाता है।

32. निर्णय की प्रतिलिपि तत्काल विचारण न्यायालय तथा संबंधित जेल प्राधिकरण को सूचना एवं आवश्यक अनुपालन हेतु भेजी जाए।

33. एल.सी.आर. को संबंधित विचारण न्यायालय में शीघ्र वापस भेजा जाए।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(शैलेन्द्र सिंह, न्यायमूर्ति)

अन्नु/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।